

दि कामक पोर्ट

वर्ष : 8, अंक : 18

(प्रति बुधवार), इन्दौर, 21 दिसंबर 2022 से 27 दिसंबर 2022

पेज : 8

कीमत : 3 रुपये

पर्यावरण मंत्रालय को भेजा गया भोपाल में यूनियन कार्बाइड स्थल से जहरीला कचरा हटाने का प्रस्ताव

नई दिल्ली, रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने भोपाल में तत्कालीन यूनियन कार्बाइड संयंत्र स्थल पर पड़े रसायनिक कचरे के निस्तारण पर मध्य प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को पर्यावरण मंत्रालय को भेज दिया है। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री बगवंत खुबा ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को बताया कि वर्ष 2010 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार, भोपाल में यूनियन कार्बाइड स्थल से रसायनिक कचरे के निस्तारण के लिए मध्य प्रदेश सरकार जिम्मेदार है।

सरकार ने मंगलवार को राज्यसभा में रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने भोपाल में तत्कालीन यूनियन कार्बाइड संयंत्र स्थल पर पड़े रसायनिक कचरे के निस्तारण को लेकर जानकारी दी है। मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार, व्यय विभाग को इसके लिए धन जारी करने का अनुरोध करने से पहले, पर्यावरण मंत्री की अध्यक्षता में गठित निगरानी समिति द्वारा जहरीले कचरे के निपटान के प्रस्ताव का समर्थन किया जाना है। मंत्री बगवंत खुबा ने कहा, “मध्य प्रदेश की राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निरीक्षण समिति द्वारा विचार और समर्थन के लिए भेजा गया है।”



महामारी के दौरान दवाओं के बढ़ते उपयोग से कार्बन उत्सर्जन में हुई वृद्धि

मुंबई कार्बन उत्सर्जन को मापने वाले शोधकर्ताओं की एक टीम ने पाया कि एक दशक में कार्बन उत्सर्जन बढ़ गया है। हालांकि, उन्होंने यह भी पाया कि कोविड-19 महामारी के दौरान गैस और बिजली से होने वाले कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है। यह शोध मध्य जापान के एक विश्वविद्यालय अस्पताल के द्वारा किया गया है।

शोधकर्ता ने कहा यदि जलवायु संकट पर कार्रवाई करनी है, तो चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन का मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। विकसित देशों में चिकित्सा उद्योग उनके कार्बन फुटप्रिंट के एक बड़े हिस्से के लिए जिम्मेदार है। उदाहरण के लिए, अमेरिका में स्वास्थ्य देखभाल अपने राष्ट्रीय कार्बन फुटप्रिंट में लगभग 10 फीसदी का योगदान करती है। चिकित्सा क्षेत्र में यूनाइटेड किंगडम जैसे देश उत्सर्जन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा 2045 तक कार्बन मुक्त बनना चाहती है। जापान भी अपने कार्बन पदचिह्न को कम करने की मांग कर रहा है। यह 2019 में ग्रीनहाउस गैसों का छठा सबसे बड़ा उत्सर्जक था, जिससे यह वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में एक प्रमुख योगदानकर्ता बन गया। वर्तमान में, सरकार ने 2030 तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को 2013 के स्तर से 26 फीसदी तक कम करने लक्ष्य रखा है। उनका अगला कदम 2050 तक कार्बन मुक्त बनना है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, एक ऐसा कारण जिसने चिकित्सा क्षेत्र द्वारा उत्पादित कार्बन उत्सर्जन को भी प्रभावित किया है, वह है कोविड-19 महामारी। इसलिए, न केवल उद्योग कार्बन उत्सर्जन में लंबे समय के रुझानों की निगरानी करना आवश्यक है, बल्कि संक्रामक रोगों के प्रकोप के कारण होने वाले नुकसान को भी निर्धारित करना जरूरी है। एक बड़े जापानी चिकित्सा संस्थान के कार्बन पदचिह्न में समय के साथ आए बदलावों का मूल्यांकन किया गया। इसके लिए, लेक्चरर ताकानोरी यामामोटो, हिकारु मोरुका और नागोया यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट स्कूल ऑफ मेडिसिन के प्रोफेसर शोइची मारुयामा के नेतृत्व में एक शोध टीम ने बिजली, गैस, पानी के उपयोग को

दर्ज किया। दवा और चिकित्सा आपूर्ति लागत और 2010 से 2021 तक संस्थान में उत्पन्न कचरे की मात्रा पर भी गौर किया गया। नागोया शहर में स्थित, नागोया विश्वविद्यालय अस्पताल जापान के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक है, जो 2000 से अधिक कर्मचारियों को रोजगार देता है और हर साल 50 लाख से अधिक रोगियों की सेवा करता है। शोध टीम ने पाया कि 2020 में समग्र कार्बन पदचिह्न 10 वर्षों में लगभग 27 फीसदी बढ़ गया था। इनमें से लगभग एक-चौथाई कार्बन उत्सर्जन बिजली की खपत से हुआ है। हालांकि अध्ययन अवधि के दौरान बिजली और गैस से उत्पन्न कार्बन उत्सर्जन में कमी आई, फिर भी अस्पताल के कुल कार्बन फुटप्रिंट में वृद्धि हुई। चूंकि नागोया विश्वविद्यालय अस्पताल उत्तर चिकित्सा देखभाल का उपयोग करता है, कार्बन उत्सर्जन में यह वृद्धि मरीजों के इलाज के लिए आवश्यक दवाइयों और चिकित्सा आपूर्ति के बढ़ते उपयोग से संबंधित हो सकती है, उनमें से कई बुजुर्ग हैं। अध्ययन के दौरान अस्पताल के कार्बन पदचिह्न में समग्र वृद्धि के बावजूद, यह कोविड-19 महामारी के पहले वर्ष में थोड़ा कम हुआ, जो केवल 2 फीसदी से अधिक था। यह 2020 में रोगियों की कम संख्या और इसके परिणामस्वरूप फार्मास्यूटिकल्स, पानी के उपयोग और गैर-चिकित्सीय कचरे में कमी के कारण था। हालांकि, अस्पताल के समग्र कार्बन फुटप्रिंट में कमी के बावजूद, कोविड-19 की गंभीरता ने अभी भी कार्बन उत्सर्जन में योगदान दिया है। महामारी के दौरान, अधिक चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता के कारण एक मरीज का औसत अस्पताल में रहने की अवधि अधिक थी। इसके अलावा, गहन देखभाल की आवश्यकता वाले रोगियों की अधिक संख्या का मतलब फार्मास्यूटिकल्स से कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि है।



क्लाइमेट चेंज मिशन शुरू करने वाला देश का पहला क्लाइमेट स्मार्ट राज्य बना तमिलनाडु

तमिलनाडु राज्य स्तरीय, क्लाइमेट चेंज मिशन प्रारंभ करने वाला तमिलनाडु देश का पहला क्लाइमेट स्मार्ट राज्य बन गया है। राज्य सरकार ने स्टेट क्लाइमेट एक्शन प्लान को लागू करने के लिए तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी जो कि एक स्पेशल परपज व्हीकल (एस.पी.वी.) है, का गठन किया है।

राज्य सरकार ने इसी वर्ष सितंबर माह में हरित तमिलनाडु और अगस्त माह में तमिलनाडु वेटलैंड मिशन की भी शुरुआत की है। राज्य मुख्यमंत्री एम.के. स्टेलियन ने कहा है कि हमारी सरकार जलवायु परिवर्तन को एक बहुत बड़े मानवीय संकट के रूप में देखती है। अत्यधिक कार्बन

एमिशन के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और वैज्ञानिकों का कहना है कि 2050 तक वैश्विक देशों को कार्बन न्यूट्रल स्टेट्स प्राप्त करना आवश्यक है। पिछले कॉप-26 में भारत सरकार ने देश को 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनाने की घोषणा की है जबकि तमिलनाडु सरकार देश द्वारा निर्धारित लक्ष्य से पहले ही राज्य को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए प्रयासरत है। पूर्णतया ग्रीनहाउस गैसेस के इमिशन को राज्य स्तर पर कम किए जाने के लिए प्लान बनाना। सार्वजनिक यातायात को बेहतर बनाने के लिए रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी का उपयोग करना। आगामी 10 वर्ष में राज्य स्तरीय बन हरित क्षेत्र को 7% से बढ़ाकर 33% किया जाना। नगरों तथा

ग्रामों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को बेहतर करना। अभूतपूर्व समुद्र तल उन्नयन और जलवायु संकट से निपटने के लिए स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर / अवसंरचना तैयार करना। सभी शैक्षणिक संस्थानों में जलवायु परिवर्तन विषय संबंधित जागरूकता कार्यक्रम चलाना। जलवायु परिवर्तन के कारण मनुष्य सहित सभी प्रकार के जीव जंतु के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक स्वास्थ्य पर बल देना। डाउन टू अर्थ ने पाया कि मानवीय, पर्यावरणीय और आर्थिक दृष्टि से जलवायु परिवर्तन और इसका नकारात्मक प्रभाव अविवादित रूप से बहुत क्षति पहुंचाने वाला है। इस कारण देश का पहला क्लाइमेट स्मार्ट राज्य बनाने वाला तमिलनाडु सरकार का यह प्रयास सराहनीय है। तमिलनाडु सरकार ने 13 लक्ष्यों इस

मिशन के तहत साधने का प्रयास पॉल्यूशन को कम करना और जैव विविधता में सुधार लाना। समुद्र तटों को मृदा अपरदन से बचाना, समुद्र आधारित तटीय बनस्पतियों को सुरक्षित करना। राज्य में ई-वेस्ट और बायोमेडिकल वेस्ट सहित नगरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को बेहतर बनाने पर जोर देना। क्लाइमेट एक्शन की दिशा में कार्य करने के लिए एक बहुत बड़ी धनराशि की आवश्यकता होती है जिसके लिए नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज और ग्रीन क्लाइमेट फंड के अतिरिक्त अन्य आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली संस्थाओं पर भी विचार किया जाना चाहिए। हालांकि राज्य सरकार ने बजट वर्ष 2021-2022 में, तमिलनाडु क्लाइमेट चेंज मिशन के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं जिसका उपयोग जलवायु परिवर्तन प्रबंधन और सुधार कार्यक्रमों के लिए किया जाएगा। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने मरीन लिटर को कम करने, कचरे / अपशिष्ट से विद्युत उत्पादन, समुद्र वनस्पति, समुद्र आधारित पर्यावास संबंधित शोध किए जाने के लिए 77.35 करोड़ रुपए आवंटित किए हुए हैं।

वैज्ञानिकों ने पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में ढूँढ़ी बॉटलनोज डॉल्फिन की नई उप प्रजाति

मुंबई वैज्ञानिकों ने पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में बॉटलनोज डॉल्फिन की नई उप-प्रजाति को खोजने का दावा किया है। यह खोज यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी के रोसेंस्टियल स्कूल ऑफ मरीन, एटमोस्फियरिक एंड अर्थ साइंस के वैज्ञानिकों ने की है।

इस बारे में खोज से जुड़ी और मरीन मैमोलॉजी में विशेषज्ञता रखने वाली शोधकर्ता एना कोस्टा का कहना है कि, हालांकि डॉल्फिन के बारे में एक आम धारणा यह है कि इसकी सभी प्रजातियां पहले से ही ज्ञात हैं, लेकिन हाल के वर्षों में जिस तरह से प्रौद्योगिकियों और पद्धतियों में सुधार हुआ है उससे कहीं ज्यादा जैव विविधता को उजागर करने में मदद मिल रही है। इस बारे में विस्तृत जानकारी जर्नल ऑफ मेमेलियन एवोल्यूशन में प्रकाशित हुआ है। नमूनों की एक श्रृंखला की जांच और विश्लेषण के बाद, शोधकर्ता कोस्टा और नेशनल ओशनिक एंड एटमोस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के उनके सहयोगियों ने पाया कि नई उप-प्रजाति, जिन्हें ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक बॉटलनोज डॉल्फिन (टर्सिओप्स ट्रॉकेटस नुआनू) कहा जाता है, अन्य सामान्य बॉटलनोज डॉल्फिन से छोटी हैं। एना का कहना है कि ये डॉल्फिन दक्षिणी बाजा कैलिफोर्निया और गैलापागोस द्वीप समूह के बीच गहरे खुले समुद्रों में रहना पसंद करती हैं।

सामान्य बॉटलनोज डॉल्फिन से कैसे अलग है यह उप-प्रजाति

यह अध्ययन 2016 में शुरू हुआ था। इन उप प्रजातियों की जांच के लिए वैज्ञानिकों ने सामान्य बॉटलनोज डॉल्फिन के नमूनों की कुल लंबाई और खोपड़ी की आकारिकी की जांच की है। यह नमूने प्रशांत महासागर से एकत्र किए गए थे और अमेरिका के कई संग्रहालय में संग्रहीत हैं। उन्होंने बॉटलनोज डॉल्फिन की आबादी के बीच पाए जाने वाले अंतरों के स्तर की जांच करने के लिए मल्टीवैरियेट और क्लस्टरिंग एनालिसिस का इस्तेमाल किया है। कोस्टा ने बताया कि इस जांच में उन्हें दो अलग-अलग मॉर्फोलॉजिकल समूह मिले। जो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर (ईटीपी) में पाई जाने वाली नई उप-प्रजातियां और मुख्य रूप से पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रशांत महासागर में पाई जाने वाली बॉटलनोज डॉल्फिन में यह अंतर शायद पानी की अलग-अलग पर्यावरणीय परिस्थितियों, जैसे ऑक्सीजन और लवणता के स्तर के साथ तापमान की स्थिति में होने वाली भिन्नता के कारण हो सकते हैं।

हरित ईधन क्या होता है, किसानों और पर्यावरण के लिए कैसे है यह लाभदायक



नई दिल्ली। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी ने एकबार कहा था कि मुझे पूरा विश्वास है कि पांच साल बाद देश से पेट्रोल खत्म हो जाएगा। आपकी कारें और स्कूटर पूरी तरह हरित ईधन (हाइड्रोजन, एथेनॉल, सीएनजी या एलएनजी) पर आधारित होंगे। वास्तव में, पर्यावरण प्रदूषण और ईधन की महंगाई दोनों ही बेहद गंभीर समस्याएँ हैं। बढ़ता वायु प्रदूषण लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल रहा है तो वहीं बढ़ती डीजल-पेट्रोल की मांग व कीमतें आम जनता को बेहाल कर रही है। जिसके निवारण में ग्रीन फ्यूल (एक अहम भूमिका निभा सकता है।

ग्रीन फ्यूल (हरित ईधन), ऊर्जा का वह स्रोत है जो उपयोग करने पर बहुत कम प्रदूषण उत्पन्न करता है। इसके एक प्रकार को जैव ईधन भी कहा जाता है। यह बायोमास यानि पौधे या शैवाल सामग्री या पशु अपशिष्ट से प्राप्त होता है। पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाशम ईधन के विपरीत, अक्षय ऊर्जा (जो प्रदूषणकारक नहीं है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायो गैस आदि) को भी हरित ऊर्जा और ईधन का एक स्रोत माना जाता है। इसे पर्यावरण के अनुकूल विकल्प के रूप में

मान्यता मिल गयी है। इसमें बायो इथेनॉल, बायो गैस, बायो डीजल, बायो हाइड्रोजन व बायो ब्यूटेनॉल आदि आते हैं।

किण्वन विधि (बायोमास को इथेनॉल में परिवर्तित करने की विधि) द्वारा बायो इथेनॉल (अक्षय ईधन/अल्कोहल) बनाया जाता है। इस विधि में सूक्ष्मजीव (बैक्टीरिया और खमीर आदि) पादप शर्करा को चयापचय कर इथेनॉल का उत्पादन करते हैं। इस विधि से गन्ना, ज्वार, मक्का, बाजरा, धान, गेहूं और दूसरे बीज-अवशेषों से भी इथेनॉल बनाया जा सकता है। इसी प्रकार बायोडीजल को सोयाबीन तेल या

ताड़ के तेल, बनस्पति अपशिष्ट तेलों और पशु वसा जैसे बनस्पति तेलों से प्राप्त किया जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल को पानी से बनाया जाता है। पानी का इलेक्ट्रोलिसिस (सोलर एनर्जी द्वारा) करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जाता है। हाईड्रोजन एक पावरफुल ईधन है, जिसको काफी मात्रा में उत्पन्न किया जा सकता है। संजय सिंह ने सदन में उठाया यूपी में तस्ङ्ग का मुद्दा, उपराष्ट्रपति ने कही यह बात संजय सिंह ने सदन में उठाया यूपी में तस्ङ्ग का मुद्दा, उपराष्ट्रपति ने कही यह बात

पर्यावरण व किसानों के लिए कैसे है लाभदायक- हरित ईधन एथेनॉल, जिसको खेतों से निकली पराली, खाद्य पदार्थों के

प्लांट लगाए जाने से रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे।

क्षमता से संबंधित विकास में मदद मिलेगी।

दुनिया को ग्रीन फ्यूल का विकल्प देने में भारत की भूमिका काफी अहम हो सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत में पर्यास मात्रा में धूप होती है, जिससे ग्रीन हाइड्रोजन को तैयार करने में मदद मिल सकती है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ को आश्रित किया है कि 2030 तक भारत कार्बन उत्सर्जन की मौजूदा मात्रा को 33-35 प्रतिशत घटा देगा और 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य भी हासिल करेगा। भारत जहां प्रतिवर्ष 20.70 लाख किलो टन (प्रति व्यक्ति 1.7 टन) कार्बन उत्सर्जन करता है, वहीं अमेरिका सर्वाधिक 1.03 करोड़ किलो टन (प्रति व्यक्ति 7.4 टन) कार्बन उत्सर्जन करता है। भारत सरकार हाइड्रोजन और अमोनिया को भविष्य के प्रमुख हरित ईधन के रूप में मान रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्रीन फ्यूल को बढ़ावा देने के अंतर्गत 75वें स्वतंत्रता दिवस अर्थात् 15 अगस्त 2021 को %राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन% प्रारंभ किया गया था। जिसका उद्देश्य जलवायु लक्ष्यों को पूरा करना तथा भारत को ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाना है। इस मिशन के अंतर्गत 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन व नवीकरणीय ऊर्जा साथ इथेनॉल उत्पादन

कीमत बहुत ज्यादा है। साथ ही

यह अधिक ज्वलनशील होता है,

जिससे सुरक्षा का खतरा बढ़ जाता है।

इसके अलावा कृषि भूमि पर खाद्यान्न उत्पादन अधिक हो, यह प्राथमिकता

छोड़कर यदि बायो फ्यूल के लिए

फसलों का उत्पादन होने लगा तो

भविष्य में देश की खाद्य सुरक्षा पर

प्रश्नचिन्ह भी लग सकता है।

आईआईसीए ने पर्यावरण सामाजिक सुशासन क्षेत्रों में प्रभावी नेतृत्व पैदा करने के लिए कार्यक्रम शुरू किया

नई दिल्ली। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स- आईआईसीए ने पर्यावरण सामाजिक सुशासन- ईएसजी क्षेत्रों में प्रभावी नेतृत्व पैदा करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। आईआईसीए, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तत्वावधान में एक स्वायत्त संस्था है।

पर्यावरण सचिव लीना नंदन कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर कल मुख्य अतिथि थीं। सुश्री नंदन ने सभा को संबोधित करते भारत में ईएसजी पेशेवरों का एक कैडर बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षित जनशक्ति समय की जरूरत है और आईआईसीए ने कॉर्पोरेट पदाधिकारियों की क्षमता निर्माण के माध्यम से उद्योगों में परिवर्तन की जरूरतों को पूरा करने के लिए समय पर पहल की है। उन्होंने पर्यावरण संश्करण के अनुकूल कैडर बनाने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान का उल्लेख किया। आईआईसीए के महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण कुमार ने कहा कि आईआईसीए ने ईएसजी पेशेवरों के लिए सदस्यता-आधारित नेशनल एसोसिएशन ऑफ इम्पैक्ट लीडर्स का भी गठन किया है।



अब एक किलक में मिलेगी नर्सरी में मौजूद पौधों की जानकारी

बाड़मेर, बन विभाग की नर्सरी में पौधों की जानकारी विभाग की वेबसाइट पर अब केवल एक किलक पर मिल जाएगी। प्रदेश के सभी जिलों में स्थापित नर्सरियां अब ऑनलाइन कर दी गई हैं। नर्सरी में कितने पौधे और कौन-कौन सी किस्म उपलब्ध हैं, इसकी पूरी जानकारी एक किलक में मिल जाएगी। सरहदी बाड़मेर जिले में बन विभाग की 16 नर्सरियों को ऑनलाइन किया गया है। ऐसे में अब पर्यावरण प्रेमी घर बैठे ही नर्सरी में पौधों की उपलब्धता और किस्मों की जानकारी ले सकता है।

पाकिस्तान की सीमा पर बसे सरहदी बाड़मेर में अब लोगों को बन विभाग की नर्सरी तक जाकर समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए बन विभाग ने जिले की सभी 16 नर्सरियों को ऑनलाइन कर दिया है। इससे अब घर बैठे ही एक किलक में पौधे की किस्म व संख्या का पता कर सकते हैं। दरअसल बन विभाग सालभर नर्सरी में पौधे तैयार करता है। लोग नर्सरी में अपनी पसंद के पौधे खरीदने के लिए आते हैं। यहां सरकार की ओर से तय दर पर पौधे मिलते हैं, जिसके कारण पर्यावरण प्रेमी और आमजन सरकारी नर्सरी से पौधे खरीदना पसंद करते हैं। लेकिन कई बार नर्सरी पहुंचने पर पता चलता था कि यहां पर उनकी पसंद वाला पौधा उपलब्ध ही नहीं है। ऐसे में उन्हें निराश लौटना पड़ता था। लेकिन अब पौधों की संख्या और किस्म ऑनलाइन होने से एक किलक में ही जानकारी मिल जाएगी।

एयर क्लालिटी ट्रैकर-दरभंगा-कटिहार सहित 12 शहरों में जानलेवा रही हवा, नन्देसरी से 16 गुणा ज्यादा रहा प्रदूषण

नई दिल्ली। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 21 दिसंबर 2022 को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के 182 शहरों में से केवल 8 में हवा बेहतर रही, जबकि 40 शहरों की श्रेणी संतोषजनक, 73 में मध्यम रही। वहीं 29 शहरों में वायु गुणवत्ता का स्तर खराब दर्ज किया गया, जबकि दिल्ली-औरंगाबाद (बिहार) सहित 21 शहरों में वायु गुणवत्ता का स्तर बेहद खराब रहा। वहीं बेगूसराय 464, बेतिया 416, भागलपुर 405, छपरा 402, दरभंगा 433, कटिहार 430, पटना 402, पूर्णिया 404, राजगीर 416, सहरसा 422, समस्तीपुर 408 और सिवान 401 में वायु गुणवत्ता गंभीर दर्ज की गई।

यदि दिल्ली-एनसीआर की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में है। दिल्ली में एयर क्लालिटी इंडेक्स 328 दर्ज किया गया है। दिल्ली के अलावा फरीदाबाद में एयर क्लालिटी इंडेक्स 333, गाजियाबाद में 262, गुरुग्राम में 340, नोएडा में 312 पर पहुंच गया है। देश के अन्य प्रमुख शहरों से जुड़े आंकड़ों को देखें तो मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक 189 दर्ज किया गया, जो प्रदूषण के मध्यम स्तर को दर्शाता है। जबकि कोलकाता में यह इंडेक्स 295, चेन्नई में 120, बैंगलोर में 80, हैदराबाद में 113, जयपुर में 130 और पटना में 402 दर्ज किया गया।

परागण में कमी से फल-सब्जियों के उत्पादन में 5 फीसदी की कमी, हर साल 4.27 लाख मौतें

कानपुर परागण की कमी के चलते फल, सब्जियों, बादाम और अखरोट जैसे कड़े छिलके वाले फलों के उत्पादन में पांच फीसदी तक की गिरावट आ रही है। शोधकर्ताओं ने जानकारी दी है कि यह गिरावट हर साल और

427,000 लोगों की जान ले रही है। रिसर्च के मुताबिक यह मौतें स्वस्थ भोजन को होते नुकसान और उनसे होने वाली बीमारियों जैसे हृदय रोग, स्ट्रोक, मधुमेह, और कैंसर आदि के चलते हो रही हैं।

पैदावार को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखा जाए तो परागण करने वाले यह जीव फल, सब्जियों और नट्स जैसे स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों की पैदावार के लिए मायने रखते हैं। रिसर्च के मुताबिक भूमि उपयोग

खाद्य उत्पादन में आई गिरावट कम आय वाले देशों में केंद्रित थी, वहीं इसका स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा बोझ मध्यम और उच्च आय वाले देशों में दर्ज किया गया है। इन देशों में गैर-संचारी रोगों की दर अधिक है। वैश्विक पर्यावरण में आते बदलावों से स्वास्थ्य पर पड़ता प्रभाव दक्षिण एशिया और उप-सहारा अफ्रीका जैसे देशों में केंद्रित हैं जहां कमजोर आबादी इससे सबसे ज्यादा बोझ मध्यम आय वाले देशों जैसे भारत, चीन, इंडोनेशिया और रूस झोलना पड़ रहा है।

विश्लेषण से यह भी पता चला है कि कम आय वाले देशों ने अपर्याप्त परागण और कम पैदावार के चलते अपनी महत्वपूर्ण कृषि आय खो दी है, जोकि उनकी कुल कृषि मूल्य का 12 से 31 फीसदी हिस्सा है। जर्नल बन अर्थ में प्रकाशित एक अन्य अध्ययन से पता चला है कि परागणकों में आ रही है गिरावट के चलते करीब 90 फीसदी जंगली पौधों का अस्तित्व खतरे में है। इतना ही नहीं यह नहीं जीव दुनिया की करीब 85 फीसदी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण फसलों के लिए भी बहुत मायने रखते हैं। गैरतलब है कि परागण करने वाली यह मधुमेहियां और अन्य छोटे कीट दुनिया के करीब 35 फीसदी खाद्य उत्पादन में अपना योगदान देते हैं। इतना ही नहीं शोधकर्ताओं के मुताबिक दुनिया भर में करीब 200 करोड़ छोटे किसानों की पैदावार के लिए इन छोटे जीवों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाएं विशेष रूप से मायने रखती हैं। ऐसे में अध्ययन से जुड़े शोधकर्ताओं मैथ्रूस्मिथ का कहना है कि जंगली परागणकर्ताओं को बचाने की रणनीति न केवल पर्यावरण बल्कि स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा मुहावरा है। ऐसे में इन परागणकर्ताओं को बचाने के प्रयासों में दी गई ढील न केवल प्रकृति बल्कि इंसानी स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचा सकती है।

